

## हरियाणा बकाया जल शुल्क माफ करेगा

### चर्चा में क्यों?

हाल ही में मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता वाली कैबिनेट बैठक में राज्य में ग्रामीण परिवारों के लिये **₹372.13 करोड़ बकाया जल शुल्क**, जसमें अधभार (सरचारज) और ब्याज भी शामिल है, माफ करने का नरिणय लयिा गया ।

### मुख्य बदि:

- सूत्रों के मुताबकि इस छूट से **28.87 लाख जल कनेक्शन धारकों** को फायदा होगा । यह सार्वजनिक स्वास्थ्य इंजीनियरिंग वभिाग के अंतर्गत आने वाले संस्थागत, वाणजियकि या औद्योगकि उपभोक्ताओं पर लागू नहीं होता है ।
- कैबिनेट ने ग्रामीण कषेत्रों के सभी प्रकार के उपभोक्ताओं के लयिे 1 अप्रैल 2015 से 31 दसिंबर 2022 तक जमा 336.35 करोड़ रुपए की पेयजल शुल्क माफी को मंजूरी दे दी है ।
  - इसमें सामान्य वर्ग के साथ-साथ अनुसूचति जात विरग भी शामिल है ।
- पर्यावरण पर्यटन नीतकि वकिस को भी मंजूरी दी गई है । यह नीत हरियाणा के वविधि परदृश्यों के संरक्षण पर ज़ोर देती है ।
- इनमें दो राषटरीय उद्यान, सात वन्यजीव अभयारण्य, दो रामसर स्थल, दो संरक्षण रजिर्व और पाँच सामुदायकि रजिर्व शामिल हैं ।
  - इसमें बहुत से वशिषिट पशु आवास पारस्थितिकि तंत्र भी शामिल हैं, जनिमें अरावली परवत शृंखला, शवालकि पहाड़ियाँ, समृद्ध जैववविधिता, सघन जंगल, जल नकियाय और दर्शनीय स्थल शामिल हैं ।